उमेश सिंह

बनाम

बिहार राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 43/2010)

22 मार्च, 2013

[चंद्रमौली के. आर. प्रसाद और वी. गोपाल गौड़ा, जे.जे.,]

दंड संहिता, 1860-धारा 302 सपठित धारा 34 - हत्या-मृतक को रिवॉल्वर और राइफल से गोली मारी गई थी-कई आरोपी- अभियुक्त-अपीलार्थी-का दोषसिद्धि-औचित्य-निर्धारित न्यायसंगत - संबंधित चश्मदीद गवाह (पीडब्लू2) के बयान को सही ढंग से प्राथमिकी माना गया-पीडब्लू2 के साक्ष्य को अन्य गवाहों द्वारा समर्थित किया गया (पी. डब्ल्यू. 3, पी. डब्ल्यू. 5 और पी. डब्ल्यू. 7)-अपीलार्थी का दावा कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था, कानूनी आधार पर मान्य नहीं है।

अभिलेख पर साक्ष्य और उसी के उचित मूल्यांकन पर उसकी दोषसिद्धी आधारित। शस्त्र अधिनियम - धारा 27.साक्ष्य-मृत्युजनित कठोरता-मृत्यु का समय- 36 घंटे के बाद मृतक के शरीर से मृत्युजनित कठोरता के पूरी तरह से गायब होने के बारे में डॉक्टर की राय- शुद्धता-निर्धारित- सही नहीं है। चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सा के नियम के विपरीत साक्ष्य दी। तथ्यों पर-यह अभियुक्त की दोषमुक्ति का आधार नहीं हो सकता है।

साक्ष्य-चिकित्सा और चक्षुदर्शी साक्षी के बीच विसंगति-प्रभाव-निर्धारित- मेडिकल और चक्षुदर्शी के बीच चक्षुदर्शी साक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि जबकि मृतक अपने चचेरे भाई (पीडब्लू2) के साथ बस पकड़ने जा रहा था, आरोपी-अपीलार्थी और अन्य आरोपी अवधेश सिंह, सुधीर सिंह, जड्डू सिंह,

नवल सिंह, बिंदा सिंह ने मृतक को घेर लिया। उसकी रिवाल्वर एवं रायफल से गोली मारकर हत्या कर दी।विचारण न्यायालय (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) ने अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 में दोषसिद्ध किया और धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया। उच्च न्यायालय ने अवधेश सिंह, जड्डू सिंह और नवल सिंह के संबंध में धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता मे दोषसिद्धी एवं दण्डादेश को अपास्त कर दिया। और अपीलार्थी के संबंध में दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

इस अपील में, अपीलार्थी ने उसे चुनौती दी

न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1 पीडब्ल्यू 2 जो कि मृतक का भाई था घटना की दिनांक को उसके साथ था। उस समय अपीलार्थी ने अन्य अभियुक्तगण के साथ उनको घेर लिया और यह कहा गया कि अपीलार्थी ने रिवाल्वर से कनपट्टी पर गोली मारी और अन्य अभियुक्त बिंदा सिंह ने रायफल से मृतक के पेट में तथा सुधीर सिंह ने रायफल से बांयी जांघ में गोली मारी। गवाह पी डब्ल्यू 7 ने अपनी साक्ष्य में कहा कि उक्त अभियुक्तगण भाग गये जब अशोक सिंह, दामोदर सिंह, बलराम सिंह और श्याम सुंदर सिंह बाजार जा रहे थे जिन्होंने इस घटना को देखा है। उसकी साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 3 की साक्ष्य से समर्थित है जिसने अपनी साक्ष्य में कहा है कि मोतीसिंह और जड्डूसिंह ने मृतक के दोनो हाथो को पकड रखा था और मोतीसिंह ने उस पर गोली चलाने का आदेश दिया और उक्त गवाह ने भी गोली चलाने के बारे में बताया अवधेश सिंह और नवल सिंह जैसा कि पीडब्लू 2 ने कहा है। आगे इस गवाह ने कथन किया है कि अवधेश सिंह ने मृत शरीर को धकेल दिया और यह भी कहा है कि मोती सिंह एवं जड्डू सिंह ने उसको पकड लिया। पीडब्लू5 ने भी देखने का दावा किया जड्डू सिंह और मोती सिंह ने मृतक

के हाथ पकड लिये और उमेंश सिंह अपीलार्थी ने मृतक की कनपट्टी पर फायर किया। आगे उसने कहा कि बिंदा, सुधीर, अवधेश और नवल ने भी अपनी रायफलो से मृतक पर गोली चलाई। पीडब्ल्यू 2 की साक्ष्य पी डब्ल्यू 3, 5 व 7 से समर्थित है। जहां तक पीडब्ल्यू 6 का प्रश्न है उसने सामान्य कथन किया है कि उसने कई व्यक्तियों को मृतक को घेरे हुए तथा उसे रायफल और रिवाल्वर से मारते हुए देखा। अतः विचारण न्यायालय अपीलार्थी पर आरोपित अपराध की साक्ष्य के संबंध में चश्मदीद गवाह पीडब्ल्यू 2,3 व 5 पर आधारित करने में सही था। इस अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ धारा 302 के साथ पठित धारा 34 आईपीसी के आरोप पर तथ्य की उक्त निष्कर्ष की उच्च न्यायालय द्वारा गंभीरता से जांच की गई और उससे सहमति व्यक्त की गई और पीडब्लू2 और पीडब्लू9 के साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, मुखबिर जो चश्मदीद गवाह था और आईओ के साक्ष्य के संबंध में पीडब्लू2 के बयान को एफआईआर के रूप में मानना पूरी तरह से कानूनी और वैध है। [पैरा 14] [815-डी-एच; 816-ए-ई]

1.2. डॉक्टर-पीडब्लू8 ने राय दी कि मृत्युजनित कठोरता मृत्यु के 1 से 3 घंटे के भीतर शुरू हो जाती है और 36 घंटे के बाद गायब हो जाता है। डॉक्टर की यह राय कि मृत्युजनित कठोरता 36 घंटे के बाद गायब हो जाती है सही नहीं है। यह उसके ज्ञान की कमी है और उससे इस संबंध में प्रतिपरीक्षा उदार रूप से की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सा के नियम के विपरीत कथन किया है इसलिये वह अभियुक्त की दोषमुक्ति का आधार नहीं हो सकता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बी. एल. बंसल द्वारा लिखित मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस डाइजेस्ट का उल्लेख किया है, जो स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मृत्युजनित कठोरत 12 से 24 घंटे तक बनी रहती है। तत्पश्चात कम हो जाती है लेकिन इसका मतलब है कि जितनी तेजी से मृत्युजनित कठोरता प्रकट होती है, उतना ही कम समय यह बनी रहती है। इसके अलावा, अतिरिक्त सत्र

न्यायाधीश ने ठीक ही कहा है बोलिन हुल्डर मामले को संदर्भित किया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भारत के समान वातावरण में, मृत्यृजनित कठोरता एक से दो घंटे में शुरू होतर है और 18 से 24 घंट गायब होने लगती है। अपीलार्थी द्वारा दावा कि मृतक को पूर्ववर्ती समय पर मार दिया गया है और आरोप है कि आरोपी को गलत तरीके से फंसाया गया है। मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा वैध और ठोस कारण अभिलिखित करते हुए निर्णय पारित किया गया है। राज्य के अधिवक्ता ने सही कहा है कि यदि चिकित्सा और चक्षुदर्शी साक्ष्य विपरीत हैं तो चक्षुदर्शी साक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। [पैरा 16] [819-बी-ई; 820-ए-डी]

अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) एससीसी 259 2010 (13) एस. सी. आर. 311 और बूलिन हुल्डर बनाम राज्य 1996 सीआरएलजे 513-पर निर्भर था।

ए. पी. राज्य बनाम पुनती रामुलु (1994) पूरक 1 एससीसी 590 एस. सी. आर. 942; देव पूजन ठाकुर बनाम बिहार राज्य (2005) ब्तस.स्.श्र. पटना 1263; थंगावेलू बनाम। तमिलनाडु राज्य (2002) 6 एस. सी. सी. 498; मोती वी उत्तर प्रदेश राज्य (2003) 9 एस. सी. सी. 444; कुंजू मोहम्मद। वी. राज्य केरल (2004) 9 एस. सी. सी. 193; विरेंद्र बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 16 एससीसी 582रू 2008 (14) एससीआर 706; बासो प्रसाद बनाम। की स्थिति बिहार (2006) 13 एससीसी 65रू 2006 (9) पूरक। एससीआर 431; बिनय कुमार बनाम। बिहार राज्य (1997) 1 एससीसी 283रू 1996 (8) पूरक। एस. सी. आर. 225 और दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य (2008) 8 एससीसी 270रू 2008 (11) एस. सी. आर. 843-उद्धृत।

बी. एल. बंसल अधिवक्ता द्वारा चिकित्सा न्यायशास्त्र डाइजेस्ट, (1996 पृष्ठ 422 पर संस्करण)-संदर्भित।

2. दोषसिद्धि और अधिरोपित सजा का आदेश अपीलार्थी के विरुद्ध कानूनी साक्ष्य के आधार पर है। वही कानून में गलत नहीं है क्योंकि निष्कर्ष का वैध और ठोस कारण अभिलिखित करते हुए समर्थन किया गया है।

मामला कानून संदर्भः

(1994) पूरक 1 एसएससी 590	के	पैरा सं 4 से
(2009) 14 एसएससी 541	के	पैरा सं 5 से
2001 (3) एससीआर 942	के	पैरा सं 6 से
(2005) क्रि.एल.जे. पटना 1263	के	पैरा सं 6 से
(2002) 6 एसएससी 498	के	पैरा सं 8 से
(2003) 9 एसएससी 444	के	पैरा सं 8 से
(2004) 9 एसएससी 193	के	पैरा सं 8 से
2008 (14) एससीआर 706	के	पैरा सं 8 स
2006 (9) पूरक एससीआर 431	के	पैरा सं 8 से
1996 (8) पूरक एससीआर 225	के	पैरा सं 10 से
2008 (11) एससीआर 843	के	पैरा सं 11 से
2010 (13) एससीआर 311	पर निर्भर	पैरा संख्या 15
1996 सीबारएलएलजे 513	पर निर्भर	पैरा संख्या 16

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 43/2010

पटना उच्च न्यायालय, के आपराधिक अपील संख्या 318/1998 में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.05.2003 से उत्पन्न ।

अमरेंद्र शरण, समीर अली खान, ध्रुव पाल, सोमेश चंद्र झा, अपराजिता मुखर्जी अपीलार्थी की ओर से।

चंदन कुमार, गोपाल सिंह, प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय, न्यायधीश वी. गोपाल गौड़ा, जे. द्वारा पारित किया गया :-

1. यह अपील अपीलकर्ता द्वारा क्रि.अ. सं. 241, 247, 271 व 318/1998 में पारित सामान्य निर्णय दिनांक 22 मई 2003 से व्यथित होकर दायर की गई है। आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए विभिन्न तथ्यों और कानूनी तर्कों का आग्रह किया गया। यहां अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 1998 के क्रि.अ. संख्या 318 में अपीलकर्ता था। उक्त मामले में पारित आक्षेपित निर्णय इस अपील में चुनौती के अधीन है।

2. अभियोजन मामले के संबंध में संक्षिप्त तथ्य यहां उन प्रतिद्वंद्वी कानूनी तर्कों की सराहना करने के लिए दिए गए हैं, जो पक्षकारो की ओर से यह पता लगाने के लिए आग्रह किए गए हैं कि क्या इस न्यायालय को दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाई गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

3. मृतक शैलेन्द्र कुमार की हत्या दिनांक 16.07.1996 को लगभग 3.30 बजे अपरान्ह अपीलार्थी उमेश सिंह एवं अन्य व्यक्तियों अर्थात् अवधेश सिंह, सुधीर सिंह, जद्दू सिंह, नवल सिंह, बिन्दा सिंह उर्फ बिन्देश्वरी सिंह ने रिवाल्वर से गोली मारकर कर दी थी। और अन्य अभियुक्तों के साथ आम इरादे को आगे बढ़ाने के लिए गैरकानूनी उद्देश्य के लिए आपराधिक इरादे से राइफल और उनके कब्जे में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल आरोपी नंबर 5 और के साथ शैलेन्द्र कुमार की हत्या करने

के लिए एक गैरकानूनी उद्देश्य के लिए करने के इरादे से किया गया था। और दूसरा आरोपी मोती सिंह जो मर चुका है, उन पर आईपीसी की धारा धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत आरोप लगाए गए । अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक अपने चचेरे भाई अरविंद कुमार.पीडब्ल्यू 2 के साथ 16.07.1996 को लगभग 3.30 बजे कोठार के लिए बस पकड़ने के लिए तुंगी जा रहे थे, जब वे लतावर पयीन के पास तुंगी हाई स्कूल से कुछ दूरी पर आगे बढ़े। उपरोक्त आरोपियों ने उन्हें घेर लिया। मृतक आरोपी मोती सिंह पर आरोप है कि उसने अपने अन्य साथियों को मृतक शैलेन्द्र कुमार को गोली मारने के लिए उकसाया था, जिस पर अपीलकर्ता ने एक देशी रिवॉल्वर निकाली और मृतक की कनपटी में गोलियां दाग दीं और आरोपी नंबर 2 जिसके पास राइफल थी उसके हाथ में मृतक के पेट में गोली लगी। आरोपी नंबर 4 ने भी गोली चलाई जिससे मृतक के पैर में चोट आई जबकि आरोपी नंबर 3 ने भी अपनी राइफल से गोली चलाई। आरोपी नंबर 5 के पास भी राइफल थी और उसने मृतक के शव को पईन में फेंक दिया। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि घटना के दौरान सूचक पीडब्ल्यू 2 अरविंद कुमार को मृतक आरोपी मोती सिंह और जड्डू सिंह ने अपने कब्जे में रखा और लक्ष्य पूरा करने के बाद वे चले गए। इसके अलावा जिन गवाहों के नाम बयानसूचि में पाए गए, उन्होंने घटना को घटित होते हुए देखने का दावा किया। एएसआई आरएस सिंह द्वारा उसी तिथि को लगभग 7.00 बजे शाम को तुंगी हाई स्कूल छात्रावास, लतावर पाईन में फर्दबयान दर्ज किया गया था और शव की जांच रिपोर्ट भी शाम 7.10 बजे घटना स्थल पर ही तैयार की गई थी। कुछ आपत्तिजनक वस्तुओं की जब्ती सूची मौके से बरामद किये गये खाली कारतूसों सहित अन्य सामग्री भी तैयार कर ली गयी है। औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई। जांच पूरी होने पर पुलिस ने विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उनके द्वारा संज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपनी बारी पर

मामले को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवादा की फाइल में स्थानांतरित कर दिया और धारा 302 सपठित धारा 34 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के लिए आरोप तय किए गए, अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया। मामला सुनवाई के लिए चला गया और अभियोजन पक्ष ने गवाहों पीडब्ल्यू 1 से पीडब्ल्यू 9 तक को परिक्षीत करवाया और बचाव के समर्थन में दो गवाहों को परिक्षीत करवाया गया। साक्ष्य और रिकॉर्ड के मूल्यांकन पर विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 04.04.1998 को फैसला सुनाया जिसमें आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धारा 302 के साथ धारा 34 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषसिद्धि और सजा सुनाई गई और आईपीसी की धारा 302 के साथ पठित 34 के तहत आजीवन कारावास। विभिन्न आरोपों के तहत दोषसिद्धि के संबंध में दी गई सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा को अभियुक्तों ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्वोक्त अपीलों में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने सभी अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को सुनने के बाद वर्तमान अपीलकर्ता के संबंध में दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए सामान्य निर्णय पारित किया और अब तक अवधेश सिंह, जड्डू सिंह और नवल सिंह की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया, जिन्हें अपील संख्या 241/98 और 247/98 में आईपीसी की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत आरोपों का दोषी नहीं माना गया था। हालाँकि जहाँ तक वर्तमान अपीलकर्ता और अन्य का सवाल है विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की गई थी। अपील के लंबित रहने के दौरान मोती सिंह नाम के अभियुक्त की मृत्यु हो गई और उसकी अपील निरस्त हो गई।

4. अपीलकर्ता ने अन्य लोगों के साथ उसके खिलाफ दी गई सजा और सजा की पुष्टि में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में दर्ज निष्कर्षों की शुद्धता पर सवाल उठाया है। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अमरेंद्र शरण का

तर्क है कि उच्च न्यायालय अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियों को नोटिस करने में विफल रहा है वह इस पर अविश्वास कर सकता था लेकिन उसने इस अपीलकर्ता पर दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की है। इसके अलावा यहां तक कि अपने स्वयं के निष्कर्षों के अनुसार घटना की घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था क्योंकि पीडब्ल्यू घटना के 15.20 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचे और मौके पर मौजूद मुखबिर ने अपीलकर्ता की भूमिका के संबंध में साक्ष्य और एफआईआर में अलग.अलग बयान दिया है। पीडब्लू 2 अरविंद कुमार, जो मृतक का चचेरा भाई है, का बयान वह आधार है जिस पर एफआईआर दर्ज की गई थी और मामले की जांच अधिकारी द्वारा की गई थी। पीडब्लू 2 घटना के समय मौजूद था और उसके बयान के आधार पर, आरोपी व्यक्तियों को उसके बयान को एफआईआर मानकर झूठा फंसाया गया है, यह विलंबित एफआईआर है जो कानून में स्वीकार्य नहीं है और धारा 162, सीआरपीसी के तहत भी बाधित है। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने एपी राज्य बनाम पुनाती रामुलु (1994) पूरक 1 एससीसी 590 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है। {1, प्रासगिंक पैराग्राफ इस प्रकार हैं-

> "3. हमारी राय में उत्तरदाताओं को बरी करने की रिकॉर्डिंग के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कारण साक्ष्य की उचित सराहना पर आधारित हैं। निष्कर्ष न केवल साक्ष्य की उचित सराहना द्वारा समर्थित हैं बल्कि उचित और ठोस भी हैं। दागी जांच के कारण, कृष्ण राव की हत्या पर कोई सज़ा नहीं मिलती। लेकिन हमें यह जोड़ने में जल्दबाजी करनी चाहिए कि चूंकि बचाव पक्ष पुलिस जांच की प्रामाणिकता को सफलतापूर्वक चुनौती देने में सक्षम रहा है, इसलिए इसने अभियोजन पक्ष के अन्य सबूतों की विश्वसनीयता को भी कम कर दिया है।

5. एक बार जब हमें पता चलता है कि जांच अधिकारी जानबूझकर प्रकृति के संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहा है, जैसा कि इस मामले में है, और उचित विचार.विमर्श के बाद घटनास्थल पर पहुंचने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की थी। यह निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है कि जांच दागदार है और इसलिए ऐसी दागी जांच पर भरोसा करना असुरक्षित होगा क्योंकि किसी को नहीं पता होगा कि पुलिस अधिकारी ने सबूत गढ़ने और झूठे सुराग बनाने के लिए कहां रुका होगा। हालाँकि हम इस बात से सहमत हैं कि केवल गवाहों पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 मृतक के बच्चों या पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 का रिश्ता, जो मृतक से भी संबंधित हैं, उनकी गवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है और यह रिश्ता या सबूतों की पक्षपातपूर्ण प्रकृति ही अदालत को सबूतों की अधिक सावधानी से जांच करने के लिए तैयार करती है, हम पाते हैं कि इस मामले में जब जांच की प्रामाणिकता पर सफलतापूर्वक हमला किया गया है, तो इन गवाहों की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा या तो दृढ़ प्रकृति के मजबूत पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में जो इस मामले में वांछित पाया गया है।

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि पीडब्लू 4 द्वारा पुलिस को दी गई पूर्व सूचना को दबा दिया गया था और उस समय तक पीडब्लू 9.आईओ घटना स्थल पर पहुंच चुका था, अन्य पुलिस अधिकारी और जिले के एसपी वहां मौजूद थे। मामले में आरोपियों के खिलाफ अभियोजन का मामला साबित करने के लिए उनसे पूछताछ नहीं की गई। अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में उपरोक्त व्यक्तियों से पूछताछ न करना जो अभियोजन मामले को साबित करने के लिए

महत्वपूर्ण गवाह हैं, मामले के लिए घातक है जैसा कि इस न्यायालय ने मुसाउद्दीन अहमद बनाम असम राज्य (2009) 14 एससीसी 541 में रिपोर्ट किए गए मामले में माना है। उपर्युक्त मामले का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है-

> "11. यह पार्टी का कर्तव्य है कि वह अपने पास सबसे अच्छे साक्ष्य का नेतृत्व करे जो विवाद में मुद्दे पर प्रकाश डाल सके और यदि ऐसे भौतिक साक्ष्य को रोक दिया जाता है, तो अदालत साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 दृष्टांत ;जी के तहत प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है । इस बात के बावजूद कि सबूत देने की ज़िम्मेदारी ऐसी पार्टी पर नहीं थी और उसे उक्त सबूत पेश करने के लिए नहीं कहा गया था ; गोपाल कृष्णजी केतकर बनाम मोहम्मद हाजी लतीफ़ के मामले में।"

6. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पीडब्लू4 द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी को एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं किया जा रहा है, बल्कि मामले में पीडब्ल्यू2 की जानकारी को एफआईआर के रूप में माना जा रहा है, हालांकि यह सीआरपीसी की धारा 162 के तहत बाधित है । अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह पैदा करता है और इसलिए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके समर्थन में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले टीटी एंटनी बनाम केरल राज्य(2001) 6 एससीसी 181 पर भरोसा किया है। प्रासंगिक पैराग्राफ यहां निकाले गए हैं-

> "18. सीआरपीसी की धारा 154 की उपधारा (1) के तहत दी गई जानकारी को आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट ;एफआईआर) के रूप में जाना जाता है, हालांकि इस शब्द का उपयोग संहिता में नहीं किया गया है । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है. और जैसा कि इसके उपनाम से पता चलता हैए यह किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी

अधिकारी द्वारा दर्ज की गई संज्ञेय अपराध की सबसे प्रारंभिक और पहली सूचना है। यह आपराधिक कानून को गति प्रदान करता है और जांच की शुरुआत को चिह्नित करता है जो धारा 169 या 170 सीआरपीसी के तहत राय के गठन, जैसा भी मामला हो, और धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक पुलिस रिपोर्ट को अग्रेषित करने के साथ समाप्त होता है। यह बिल्कुल संभव है और ऐसा अक्सर नहीं होता है कि एक या एक से अधिक संज्ञेय अपराधों से जुड़ी एक ही घटना के संबंध में एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी को एक से अधिक सूचनाएं दी जाती हैं। ऐसे मामले में उसे उनमें से प्रत्येक को स्टेशन हाउस डायरी में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और यह सीआरपीसी की धारा 154 में निहित है। फोन कॉल या गुप्त टेलीग्राम द्वारा अस्पष्ट जानकारी के अलावा, किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए रखी गई स्टेशन हाउस डायरी में सबसे पहले दर्ज की गई जानकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट है. धारा 154 द्वारा दर्ज की गई एफआईआर सीआरपीसी. संज्ञेय अपराध की जांच शुरू होने के बाद मौखिक या लिखित रूप से दी गई अन्य सभी सूचनाएं प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से प्रकट होती हैं और पुलिस अधिकारी द्वारा स्टेशन हाउस डायरी में दर्ज की जाती हैं या ऐसे अन्य संज्ञेय अपराध जो उसके ध्यान में आ सकते हैं जांच के दौरान सीआरपीसी की धारा 162 के तहत बयान दिए जाएंगे । ऐसी किसी भी जानकारी/बयान को उचित रूप से एफआईआर के रूप में नहीं माना जा सकता है और स्टेशन हाउस डायरी में दोबारा दर्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह वास्तव में दूसरी एफआईआर होगी और यह सीआरपीसी की योजना के अनुरूप नहीं हो

सकती है । ऐसे मामले को लें जहां एफआईआर में आईपीसी की धारा 307 या 326 के तहत संज्ञेय अपराध का उल्लेख है और जांच एजेंसी को जांच के दौरान पता चलता है या ताजा जानकारी मिलती है कि पीड़ित की मृत्यु हो गई है, धारा 302 आईपीसी के तहत कोई नई एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है जो अनियमित होगी, ऐसे मामले में पहली एफआईआर में कानून के प्रावधान में बदलाव करना उचित कदम है। एक अलग स्थिति पर विचार करें जिसमें एच ने अपनी पत्नी डब्ल्यू को मार डाला है, पुलिस को सूचित किया है कि उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने मार डाला है या यह जानते हुए कि डब्ल्यू को उसकी मां या बहन ने मार डाला है, जिम्मेदारी लेता है और जांच के दौरान सच्चाई सामने आती है। पता चला, इसमें वास्तविक अपराधी . के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है . जिसे धारा 173(2) व 173(8) सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट में जैसा भी मामला हो दोषी ठहराया जा सकता है।जांच अधिकारी के लिए निश्चित रूप से यह अनुमति है कि वह पहले भी संबंधित मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेज सकता है कि जांच उस व्यक्ति के खिलाफ की जा रही है जिसके आरोपी होने का संदेह है।

19. सीआरपीसी की योजना यह है कि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को संज्ञेय अपराध के घटित होने का पता चलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रविष्टि के आधार पर सीआरपीसी की धारा 156 या 157 के अनुसार जांच शुरू करनी होती है। जांच पूरी होने पर और एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर, उसे धारा 169 या 170 सीआरपीसी के तहत एक राय बनानी होगी, चाहे मामला जैसा भी हो, और अपनी रिपोर्ट धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत संबंधित

मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। हालाँकि, ऐसी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी यदि उसके पास अतिरिक्त जानकारी या सामग्री आती है, तो उसे नई एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, उसे आगे की जांच करने का अधिकार है, आम तौर पर अदालत की अनुमति के साथ, और जहां आगे की जांच के दौरान वह मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करता है, वह उसे एक या अधिक अतिरिक्त रिपोर्टों के साथ अग्रेषित करने के लिए बाध्य होता है, यह धारा 173 सीआरपीसी की उपधारा (8) का आयात है ।

20. उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा 154, 155 , 156, 157, 162, 169, 170 और 173 सीआरपीसी के प्रावधानों की योजना के तहत संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में धारा 154 सीआरपीसी की आवश्यकताएँ केवल सबसे प्रारंभिक या पहली सूचना ही संतुष्ट होती है। इस प्रकार कोई दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती है और परिणामस्वरूप एक ही संज्ञेय अपराध या एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देने वाली एक ही घटना या घटना के संबंध में प्रत्येक बाद की जानकारी प्राप्त होने पर कोई नई जांच नहीं हो सकती है। किसी संज्ञेय अपराध या किसी संज्ञेय अपराध या अपराध को जन्म देने वाली घटना के बारे में सूचना प्राप्त होने पर और स्टेशन हाउस डायरी में एफआईआर दर्ज करने पर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को न केवल एफआईआर में रिपोर्ट किए गए संज्ञेय अपराध की जांच करनी होती है। बल्कि अन्य संबंधित अपराध भी एक ही लेन.देन या एक ही घटना के दौरान किए गए पाए जाते हैं और धारा 173 सीआरपीसी में दिए गए अनुसार एक या अधिक रिपोर्ट दर्ज करें।

इसके अलावा, देवपूजन ठाकुर बनाम बिहार राज्य (2005) सीआरएल एलजे पटना 1263 के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने इस प्रकार राय दी-

> "18. रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे साक्ष्य और बहस के दौरान बचाव पक्ष द्वारा लाई गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने पहली जानकारी अपने पास रखी और उसे सबसे अच्छे से ज्ञात कारणों से इसे अदालत के समक्ष पेश नहीं किया। इसने स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की, हालांकि इनमें से कुछ नामों का उल्लेख अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में किया गया है और उनमें से कुछ तब भी आरोप.पत्र के गवाह थे, केवल परिवार के सदस्यों और इच्छुक गवाहों से पूछताछ की गई है जो शत्रुतापूर्ण हैं। जिस फर्दबयान के आधार पर औपचारिक एफआईआर तैयार की गई थी, वह सीआरपीसी की धारा 162 से प्रभावित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ.साथ पीडब्लू 11 के साक्ष्य ने मामले के बचाव पक्ष के संस्करण की पुष्टि की है कि मृतक को एक सुनसान जगह पर मार दिया गया था जब वह प्रकृति की कॉल में भाग लेने के बाद आ रहा था। मामले की परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष का बयान विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा जो सबूत लाए गए हैं, वे सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहे हैं। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं है।"

7. विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि मामले में अत्यधिक रुचि रखने वाले अन्य पीडब्ल्यू से पूछताछ की गई थी। स्वतंत्र गवाह उपलब्ध थे लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में उनसे पूछताछ नहीं की गई।

इसलिए, अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए स्वतंत्र गवाहों की जांच न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत आरोप पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्ष कानून की दृष्टि से गलत है। उच्च न्यायालय पीडब्लू 2 के साक्ष्यों पर विचार करने में विफल रहा है, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक मुखबिर है। अपने साक्ष्य में उन्होंने कहा है कि शव बरामद किया गया था उसके बाद पीडब्लू 2 का बयान दर्ज किया गया था और वह अन्य गवाहों के साथ घटना स्थल पर ही रहे और उनमें से कोई भी पुलिस को सूचित करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं गया। पीडब्लू 3 दामोदर सिंह ने अपने साक्ष्य में कहा है कि कोई भी पुलिस को सूचित करने नहीं गया था लेकिन पीडब्लू 4 अशोक कुमार ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उनका बयान एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था जहां उन्होंने कहा था कि उन्होंने पुलिस को सूचना भेजी थी। पीडब्ल्यू 9 अनुसंधान अधिकारी ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि अशोक सिंह. पीडब्ल्यू 4 की सूचना पर वह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और कई अधिकारियों के साथ फर्दबयान दर्ज करने और मामला दर्ज करने से पहले घटना स्थल पर गए थे। उन्होंने आगे कहा है कि फर्दबयान को पुलिस स्टेशन भेजा गया था और फिर उन्हें आईओ बनाया गया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय कॉलम नंबर। के तहत एफआईआर में उल्लिखित मामले के प्रासंगिक पहलू पर विचार करने में विफल रहा है। फर्दबयान 7.00 बजे दर्ज किया गया था। अपराह्न और एफआईआर 16.07.1996 को रात 10.00 बजे दर्ज की गई। घटनास्थल और थाने की दूरी करीब 16 किलोमीटर है पीडब्लू 9 के अनुसारए 16.07.1996 को रात 10 बजे के बाद आईओ को बदल दिया गया था, इसलिए विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि पीडब्लू 4 अशोक कुमार और पीडब्लू 9 के साक्ष्य के आधार पर और इस न्यायालय द्वारा निर्णयों में तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में पीडब्लू 2 के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करना कानून में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सीआरपीसी की धारा 162 के अंतर्गत

आता है । पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के संबंध में उपरोक्त तथ्यों और कानूनी सबूतों के मद्देनजर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय को न्यायिक निष्कर्ष निकालना चाहिए था कि पीडब्लू 2 के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए, जो धारा 162 सी.आर.पी.सी से प्रभावित है। इस मामले के गवाहों के कहने पर अभियुक्तों के खिलाफ मामले में हेराफेरी करने और पीडब्लू4 द्वारा थाने में दी गई पहली सूचना को अफवाह बताकर दर्ज नहीं करने का परिणाम है। मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया है। इसलिएए अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ लगाए गए आरोप पर आक्षेपित निर्णय में दर्ज निष्कर्ष कानून की दृष्टि से गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावाए निचली अदालतें इस तथ्य को समझने में विफल रही हैं कि अपीलकर्ता के पास मृतक शैलेन्द्र कुमार की हत्या करने का कोई मकसद नहीं था, बल्कि इस मामले में गवाहों द्वारा आरोपी को झूठा फंसाने का मकसद था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने पीडब्लू 4 अशोक कुमार के साक्ष्य पर भरोसा किया जिसमें उन्होंने कहा है कि अवध सिंह अभियुक्त बिंदा सिंह का भाई है जिसने उसके खिलाफ मामला लाया था और आरोपी उमेश सिंह और नवल के पिता भुनेश्वर सिंह गवाह थे और पीडब्लू 5 बलराम सिंह जो गवाह थे मृतक का सगा भाई है शैलेन्द्र कुमार ने अपनी गवाही में स्वीकार किया है कि उसकी अभियुक्तों से और उसकी मृतक सहित उसके दो भाइयों से कोई दुश्मनी नहीं थी।

8. इसके अलावा विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय चिकित्सा साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहा है, जो अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना दिनांक 16.07.1996 को अपराह्न 3.30 बजे की बतायी जाती है जब मृतक अपने गांव स्थित घर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था। रिकॉर्ड पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर, कॉलम संख्या 21 से 23, पीडब्लू 8 में, डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि न केवल मृतक का

पेट बल्कि दोनों मूत्राशय खाली थे और मृत्यु के बाद का समय 30 से 36 घंटे था। इस प्रकार घटना दिनांक 16.07.1996 को तड़के घटित हुई होगी क्योंकि मृतक का पेट खाली होना चाहिए। इसके अलावा, पीडब्ल्यू 8 के साक्ष्य में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों का विवरण भी गवाहों द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुरूप नहीं है। पीडब्लू 8 डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम के समय से 30 घंटे पहले हुई होगी। इसका मतलब यह है कि घटना की कोई घटना 16.07.1996 को अपराह्न 3.30 बजे नहीं हुई थी जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था और मृतक घटना के कथित समय से पहले मर चुका था। इसलिए चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप नहीं है बल्कि यह बचाव पक्ष के संस्करण का समर्थन करता है जो पूरे अभियोजन मामले को झूठा बनाता है। इस संबंध में उन्होंने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव पर मजबूत भरोसा जताया है कि एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया मृत्यु का समय चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार काफी भिन्न होता है, तो अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है। और संदेह का लाभ अपीलकर्ता को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है, अर्थात्, थंगावेलु बनाम टीएन राज्य (2002) 6 एससीसी 498 मोती बनाम राज्य उत्तर प्रदेश (2003) 9 एससीसी 444 कुंजू मोहम्मद। बनाम केरल राज्य (2004) 9 एससीसी 193 वीरेंद्र बनाम राज्य उत्तर प्रदेश (2008) 16 एससीसी 582, और बासो प्रसाद बनाम बिहार राज्य (2006) 13 एससीसी 65.

9. इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि इस अपीलकर्ता के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए आरोप पर तथ्य की समवर्ती खोज गलत और कानून की दृष्टि से विकृत है, जिसे रद्द किया जा सकता है और उसे अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जा सकता है। और इस अपील की अनुमति देकर उसे स्वतंत्र किया जा सकता है।

10. दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री चंदन कुमार ने अन्य बातों के साथ.साथ आक्षेपित निर्णय में दर्ज निष्कर्षों और कारणों को उचित ठहराने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि उच्च न्यायालय ने अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए जांच की है अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और कारणों की सत्यता और उसके उचित मूल्यांकन पर, इसने अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की है जो अभिलेख पर आई साक्ष्य के उचित पुनः मूल्यांकन पर आधारित है। इसे वैध एवं ठोस कारणों से समर्थित किया गया है। विद्वान वकील ने पीडब्लू2 द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एफआईआर के पंजीकरण को उचित ठहराने की मांग की, जो बिनय कुमार बनाम बिहार राज्य (1997) 1 एससीसी 283 में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप है, जिसका प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है-

> "9. इस मामले में पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से प्रदर्श 10/3 को प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं मानने में हमें कोई गलती नजर नहीं आती है यह स्पष्ट रूप से एक गुप्त जानकारी है और किसी भी संज्ञेय अपराध के घटित होने का पता लगाने के लिए शायद ही पर्याप्त है। संहिता की धारा 154 के तहत जानकारी स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिए और इसे लिखित रूप में लिखा जाना चाहिए ;यदि मौखिक रूप से दिया गया हो) और इसके निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अगली आवश्यकता यह है कि उसके सार को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में पुलिस स्टेशन में रखी गई पुस्तक में दर्ज किया जाएगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट ;एफआईआर, तैयार की जानी है और इसे मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जो ऐसी रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त

किसी भी अस्पष्ट जानकारी पर एफआईआर तैयार करने के लिए बाध्य नहीं है जो संज्ञेय अपराध के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं बताता है। प्रभारी अधिकारी के लिए यह खुला है कि यदि उपलब्ध हो तो वह घटना के बारे में विवरण सहित अधिक जानकारी एकत्र कर सकता है, ताकि वह इस बात पर विचार कर सके कि क्या कोई संज्ञेय अपराध किया गया है जिसकी जांच की आवश्यकता है।''

11. इसके अलावा, आईओ के साक्ष्य पर भरोसा करके इसकी सत्यता को उचित ठहराने की कोशिश की गई है। राज्य के वकील ने दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य (2008) 8 एससीसी 270 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है। प्रासंगिक पैराग्राफ यहां निकाले गए हैं-

"11. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्लू 7 और 13 घायल गवाह थे और पीडब्लू 10 एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी था और मुखबिर था। कानून काफी अच्छी तरह से तय है कि भले ही सह आरोपी के संबंध में इस आधार पर बरी कर दिया जाता है कि अतिशयोक्ति और अलंकरण थे, फिर भी अगर किसी अन्य आरोपी के संबंध में सबूत ठोस, विश्वसनीय और सत्य पाए जाते हैं तो दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है। केवल यह तथ्य कि गवाह मृतक से संबंधित थे, उनके साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता।

12. कानून में घायल गवाह की गवाही को महत्व दिया जाता है. जब प्रत्यक्षदर्शियों को अभियुक्तों के प्रति रुचि रखने वाला और शत्रुतापूर्ण रवैया रखने वाला बताया जाता है, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि वे वास्तविक अपराधी को बचाएंगे और निर्दोष व्यक्तियों को फंसाएंगे। सबूतों की सच्चाई या

सच्चाई को व्यावहारिक रूप से तौलना होगा। अदालत को संबंधित गवाहों और उन गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी जो अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। लेकिन अगर उनके साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण और जांच के बाद, गवाहों द्वारा दिया गया बयान स्पष्ट ठोस और विश्वसनीय प्रतीत होता है, तो उसे खारिज करने का कोई कारण नहीं है। ऐसे सबूतों के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।"

12. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया घटना स्थल के संबंध में विवाद तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। घटना के स्थान के संबंध में उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए यह बहुत निश्चित है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह तुंगी में होगा। पीडब्लू 4 अशोक कुमार सिंह ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह चश्मदीद गवाह नहीं है लेकिन अफवाहों के आधार पर उसने पुलिस को सूचित किया है। आईओ ने अपने साक्ष्य में आगे कहा है कि पीडब्लू4 एक अफवाह गवाह है और इसलिए उसकी जानकारी को एफआईआर के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए उन्होंने इस न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं है, विशेष रूप से, कानूनी साक्ष्य और रिकॉर्ड की उचित सराहना पर उच्च न्यायालय द्वारा आरोप पर समवर्ती निष्कर्ष और धारा 302 आईपीसी सपठित धारा 34 के तहत आरोप के लिए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि के संबंध में। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय से अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप न करने का अनुरोध किया है।

13. पक्षों की ओर से आग्रह की गई प्रतिद्वंद्वी कानूनी दलीलों की पृष्ठभूमि में इस न्यायालय ने इस निर्णय में ऊपर दिए गए बिंदु का उत्तर देने और निम्नलिखित

कारणों से अपीलकर्ता के खिलाफ उसी का उत्तर देने के लिए उचित रूप से विचार किया है।

14. पीडब्लू 2 अरविंद कुमार, जो मृतक का चचेरा भाई है, घटना की तारीख पर उसके साथ था। उसी समय अपीलकर्ता ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उन्हें घेर लिया और यह कहा गया कि अपीलकर्ता ने कनपट्टी में रिवॉल्वर से गोली मार दी और अन्य अभियुक्तों बिंदा सिंह ने राइफल से मृतक के पेट में और सुधीर सिंह ने राइफल से मृतक के बांयी जांघ पर गोली मार दी। पीडब्लू 7 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उपरोक्त आरोपी उस समय भाग गए जब अशोक सिंह, दामोदर सिंह, बलराम सिंह और श्याम सुंदर सिंह बाजार जा रहे थे जिन्होंने घटना देखी है। उनके साक्ष्य को अन्य गवाह अर्थात् पीडब्लू 3 के साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया है, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने मोती सिंह और जद्दू सिंह को मृतक के दोनों हाथ पकड़ते हुए देखा है और मोती सिंह ने उसे गोली चलाने का आदेश दिया था और उक्त गवाह ने भी अवधेश द्वारा गोलीबारी के बारे में बात की थी।अवधेश सिंह और नवल सिंह जैसा कि पीडब्ल्यू 2 द्वारा बताया गया है। इसके अलावा, उन्होंने अपने साक्ष्य का समर्थन किया है कि अवधेश सिंह ने शव को पईन में धकेल दिया था और यह भी कहा था कि मोती सिंह और जद्दू सिंह ने सूचना देने वाले को भी पकड़ लिया था। पीडब्ल्यू 5 ने यह भी दावा किया कि उसने जद्दू सिंह और मोती सिंह को मृतक का हाथ पकड़ते हुए देखा था और आगे उसने कहा है कि अपीलकर्ता उमेश सिंह ने मृतक के मंदिर क्षेत्र में गोली चलाई थी। आगे उन्होंने स्पष्ट बयान देते हुए कहा है कि बिंदा, सुधीर, अवधेश और नवल ने भी मृतक पर अपनी रायफल से गोलियां चलाई थीं, इसलिए, पीडब्ल्यू 2 के साक्ष्य को पीडब्ल्यू 3, 5 और 7 द्वारा समर्थित किया गया है। जहां तक पीडब्लू 6 का सवाल है, उसने एक सामान्य बयान दिया है कि उसने कई लोगों को मृतक के आसपास देखा है और मृतक को राइफल और रिवॉल्वर से मार डाला है। इसलिए, पीडब्लू3 और पीडब्लू 5 द्वारा समर्थित चश्मदीद गवाह पीडब्लू 2 के साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर अपीलकर्ता

के खिलाफ आरोप पर निष्कर्ष दर्ज करने में ट्रायल कोर्ट सही था। इस अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ धारा 302 के साथ पठित धारा 34, आईपीसी के आरोप पर तथ्यों की उच्च न्यायालय द्वारा गंभीरता से जांच की गई और उससे सहमति व्यक्त की गई और पीडब्लू 2 और पीडब्लू 9 के साक्ष्य के मद्देनजर जिस पर नजर थी. पीडब्लू 2 के बयान को एफआईआर मानने वाले गवाह और आईओ के साक्ष्य पूरी तरह से कानूनी और वैध हैं। इसलिए, अपने प्रस्तुतीकरण के दौरान विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा पूर्व में संदर्भित इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता कानून में मान्य नहीं है क्योंकि वे गलत हैं।

15. जहाँ तक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ पढ़े गए डॉक्टर.पीडब्ल्यू 8 के मेडिकल साक्ष्य का सवाल है, जिस पर अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा मजबूत भरोसा जताया गया है कि मृत्यु 30 से 36 घंटे पहले हुई होगी जैसा कि डॉक्टर की राय में था। इसका मतलब है कि यह 16.07.1996 के शुरुआती घंटों से संबंधित है, लेकिन दोपहर 3.30 बजे का नहीं, जैसा कि एफआईआर में बताया गया है। एक बार जब मृत्यु का समय अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किए गए समय से काफी भिन्न हो जाता है तो इसका मामला कानूनन ख़राब हो जाता है। उपर्युक्त तर्क के समर्थन में उपरोक्त मामलों पर इस न्यायालय के निर्णयों पर की गई मजबूत निर्भरता सभी गलत हैं क्योंकि वे अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 10 एससीसी 259 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत हैं प्रासंगिक पैराग्राफ यहां निकाले गए हैं-

"33. हरियाणा राज्य बनाम भागीरथ में इसे इस प्रकार निर्धारित किया गया था-
;एससीसी पृष्ठ 101, पैरा 15)

> "15 किसी मेडिकल गवाह द्वारा दी गई राय इस विषय पर अंतिम शब्द नहीं होनी चाहिए। ऐसी राय का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यदि राय तर्क या निष्पक्षता से रहित है, तो अदालत उस राय

पर चलने के लिए बाध्य नहीं है। आख़िरकार राय वह है जो किसी तथ्यात्मक स्थिति के संबंध में किसी व्यक्ति के मन में बनती है। यदि एक डॉक्टर एक राय बनाता है और दूसरा डॉक्टर समान तथ्यों पर अलग राय बनाता है तो न्यायाधीश के लिए वह दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार होता है जो अधिक उद्देश्यपूर्ण या संभावित हो। इसी प्रकार यदि एक डॉक्टर द्वारा दी गई राय संभाव्यता के अनुरूप नहीं है तो अदालत का उस राय पर केवल इसलिए अमल करने का कोई दायित्व नहीं है क्योंकि यह डॉक्टर ने कहा है। निःसंदेह, उन व्यक्तियों द्वारा दी गई राय को उचित महत्व दिया जाना चाहिए जो किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ हैं।"

34. भागीरथ मामले को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने माना है कि जहां चिकित्सा साक्ष्य चक्षुदर्शी से भिन्न हैं,

"यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चश्मदीदों को बाहर करने के लिए चिकित्सा गवाहों के काल्पनिक उत्तरों को अनुचित प्रधानता देना गलत होगा। जिसे स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाना था और चिकित्सा साक्ष्य को 'स्थिर' रखते हुए 'चर' के रूप में नहीं माना गया था।"

35. जहां चश्मदीदों का बयान विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, वहां वैकल्पिक संभावनाओं की ओर इशारा करने वाली चिकित्सा राय को निर्णायक नहीं माना जा सकता है। चश्मदीदों के बयान की विश्वसनीयता के लिए सावधानीपूर्वक स्वतंत्र मूल्यांकन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है, जिसे ऐसी विश्वसनीयता के परीक्षण के लिए एकमात्र कसौटी के रूप में चिकित्सा साक्ष्य सहित किसी भी अन्य सबूत के आधार पर प्रतिकूल रूप से पूर्वाग्रहित नहीं किया जाना चाहिए।

"21..... साक्ष्य को उसकी अंतर्निहित स्थिरता और कहानी की अंतर्निहित संभावना के लिए परीक्षण किया जाना चाहिएय अन्य गवाहों के विवरण को श्रेय देने योग्य माना गया, निर्विवाद तथ्यों के साथ संगति, गवाहों की 'साख' गवाह बॉक्स में उनका प्रदर्शन, उनकी अवलोकन की शक्ति, आदि। तब ऐसे साक्ष्य का संभावित मूल्य संचयी मूल्यांकन के लिए तराजू में रखे जाने योग्य हो जाता है।"

36. सोलंकी चिमनभाई उकाभाई बनाम गुजरात राज्य में इस न्यायालय ने कहा- ;एससीसी पृष्ठ 180, पैरा 13)

"13.. आमतौर पर, चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य केवल पुष्टिकारक होता है। यह साबित करता है कि चोटें कथित तरीके से ही पहुंचाई गई होंगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बचाव पक्ष चिकित्सा साक्ष्य का जो उपयोग कर सकता है, वह यह साबित करना है कि चोटें संभवतः कथित तरीके से नहीं हुई होंगी और इस तरह चश्मदीदों को बदनाम किया जा सकता है। जब तक, चिकित्सीय साक्ष्य अपनी बारी में इतना आगे नहीं बढ़ जाता कि यह चश्मदीदों द्वारा कथित तरीके से होने वाली चोटों की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर देता है, चश्मदीदों की गवाही को उसके और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच कथित असंगतता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।"

39. इस प्रकार, ऐसे मामलों में कानून की स्थिति जहां चिकित्सा साक्ष्य और चक्षुदर्शी साक्ष्य के बीच विरोधाभास है, उसे इस आशय से स्पष्ट किया जा सकता है कि यद्यपि एक गवाह की नेत्र संबंधी गवाही का साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, जब चिकित्सा साक्ष्य यह नेत्र संबंधी गवाही को असंभव बना देता

है, जो साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में एक प्रासंगिक कारक बन जाता है। हालाँकि, जहाँ चिकित्सा साक्ष्य इतना आगे बढ़ जाता है कि यह नेत्र संबंधी साक्ष्य के सत्य होने की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर देता है, वहाँ चक्षुदर्शी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।"

16. विद्वान राज्य वकील ने ठीक ही आग्रह किया है कि यदि चिकित्सा और चक्षुदर्शी साक्ष्य विपरीत हैं तो चक्षुदर्शी साक्ष्य मान्य होना चाहिए। मामले के इस पहलू पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और इस सिद्धांत को उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है। गहन चर्चा के बाद और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की उचित सराहना के बाद विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए और दिए गए निष्कर्षों और निर्णयों में यह माना गया कि डॉक्टर ने राय दी है कि मृत्युकालिक कठोरता 1 से 3 घंटों के भीतर शुरू होता है और 36 घंटों के बाद गायब हो जाता है। 36 घंटों के बाद शव से मृत्युकालिक कठोरता के पूरी तरह से गायब होने के संबंध में चिकित्सा अधिकारी पीडब्लू8 की उक्त राय चिकित्सकीय रूप से सही नहीं है और यह इस विषय पर उनके ज्ञान की कमी हो सकती है और वह बचाव पक्ष के वकील द्वारा जिरह के लिए उदार थे। इसके अलावा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बीएल बंसल एडवोकेट द्वारा लिखित मेडिकल ज्यूरिस्प्रुडेंस डाइजेस्ट ;1996 संस्करण पृष्ठ 422) का सही उल्लेख किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मृत्युकालिक कठोरता 12 से 24 घंटों तक बनी रहती है और फिर समाप्त हो जाती है लेकिन इसका मतलब यह है कि जितनी जल्दी हो सके मृत्युकालिक कठोरता जितनी अधिक प्रकट होती है, यह उतने ही कम समय तक बनी रहती है। इसके अलावा, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस न्यायालय द्वारा बूलिन हलडर बनाम राज्य 1996 सीआरएल एल जे 513 में तय किए गए मामले का उल्लेख किया है, जिसमें यह माना गया है कि भारत की समान जलवायु में, मृत्युकालिक कठोरता एक से दो घंटे में शुरू हो जाती है और 18 से 24 घंटों के भीतर गायब हो जाना शुरू हो सकती है।

इसलिए, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने माना है कि मोटे तौर पर मृत्युकालिक कठोरता जितनी तेजी से प्रकट होता है, उतना ही कम समय तक बना रहता है और आगे सही टिप्पणी की है कि मृत शरीर के पैरों के कुछ हिस्सों में मृत्युकालिक कठोरता मौजूद होंगे। चिकित्सा अधिकारी पीडब्लू8 के अनुसार मृतक की मृत्यु के समय का कोई सवाल ही नहीं है। इसे 24 घंटे से अधिक समय पहले होना चाहिए जो मृत्युकालिक कठोरता के गायब होने की अधिकतम सीमा है। चिकित्सा अधिकारी पीडब्लू 8 के उक्त दृष्टिकोण को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा गलत पाया गया और माना गया कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति के समय व्यतीत होने के संबंध में अपनी जिरह में सही ढंग से गवाही नहीं दी है। उन्होंने मृत्युकालिक कठोरता के लिए समय को 30 से 36 घंटे तक बढ़ा दिया है और आगे सही माना है कि पीडब्लू 8 चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सा न्यायशास्त्र के नियम के विपरीत अपने साक्ष्य में गवाही दी है। इसलिए विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आक्षेपित फैसले में सही कहा है कि यह आरोपी को बरी करने के लिए बचाव का आधार नहीं हो सकता है। अपीलकर्ता का यह दावा कि मृतक की हत्या 16.07.1996 की सुबह की गई है और यह आरोप कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है, को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सही ढंग से खारिज कर दिया है और इससे सहमति व्यक्त की गई है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में वैध और ठोस कारण बताकर ठीक ही, सहमति व्यक्ति की गई है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इस न्यायालय के सुप्रा संदर्भित फैसले पर भरोसा किया है कि आरोप को साबित करने के लिए चिकित्सा और नेत्र साक्ष्य के बीच नेत्र साक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सही कानूनी स्थिति है जैसा कि पीडब्लू2, पीडब्लू3, पीडब्लू5 और पीडब्लू7 के साक्ष्यों के बयान पर भरोसा करने के बाद विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों ने माना है। इसलिए हमें इस मामले के पहलू पर कोई गलत तर्क नहीं मिलते है। इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ में मामले के उपरोक्त पहलू पर विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों में कोई

दम नहीं है, जिनके निर्णयों का मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है।

17. उच्च न्यायालय के साथ.साथ विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समवर्ती निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ की गई दोषसिद्धि और दिया गया दण्डादेश रिकॉर्ड पर उपलब्ध कानूनी साक्ष्य और उसके उचित विश्लेषण के आधार पर है। इसलिए, यह कानून में गलत नहीं है क्योंकि यह निष्कर्ष वैध और ठोस कारणों से समर्थित है। उपरोक्त कारणों से इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसलिए, अपील में कोई सार नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

बी.बी.बी.

अपील ख़ारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री रविकांत जिंदल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****